प्राप्त न होने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तथा अब तक ऐसे पत्रों/पैकेटों का प्रतिशत कितना है ; और

(घ) सभी जिला मुख्यालयों को स्पीड पोस्ट सेवा तंत्र (नेटवर्क) के अन्तर्गत कब तक शामिल कर लिया जाने का विचार है ।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) (i) गुजरात में सभी 19 जिला मुख्यालयों और राजस्थान में 31 जिला मुख्यालयों में एक्सप्रेस पार्सल सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है ।

(ii) इस समय जिन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी सूची नीचे दी गई है :—

गुजरात : अमरेली, भड़ौच, डांग, गोधरा, हिमंतनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, पालनपुर, सुरेन्द्रनगर और वलसाड ।

राजस्थान : बारन, बाड़मेर, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, दुर्गापुर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक ।

(ख) स्पीड पोस्ट वस्तुओं के देरी से वितरण अथवा वितरण न होने के विषय में यदा-कदा विभिन्न स्थानों से, जिसमें गुजरात और राजस्थान भी शामिल हैं, शिकायतें प्राप्त होती हैं । जब कभी ऐसी गलतियां ध्यान में आती हैं, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उन राज्यों में कुल परियात की तुलना में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परियात	कुल परियात के संबंध में प्रतिशतता
गुजरात . . .	1992–93	1427	308936	0.04%
	1993–94	1134	411812	0.03%
राजस्थान . . .	1992–93	106	82263	0.01%
	1993–94	310	194830	0.01%

(घ) जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत एक अनवरत प्रक्रिया है और यह सेवा संभावित व्यवहार्यता और प्रचालनपरक औचित्य के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है ।

टेलीफोन डायरेक्टरी

871. **श्री गोविन्दराव आदिक :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नगरों की टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के संदर्भ में सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार को ध्यान में रखकर हर वर्ष डायरेक्टरी नहीं बन रही है; और

(ग) यदि हां, तो हर वर्ष नई डायरेक्टरी उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?